जनसत्ता

एक और कवायद

भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को एक बार फिर नीतिगत दरों में कटौती करते हुए अर्थव्यवस्था की सुस्ती तोड़ने की कोशिश की है। केंद्रीय बैंक का यह कदम इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि बाजार की हालत अच्छी नहीं है, इसलिए नीतिगत दरों में एक चौथाई फीसद की और कटौती करने जैसा कदम उठाने को मजबूर होना पड़ा है। हालांकि केंद्रीय बैंक पहले से कहता रहा है कि जरूरत पड़ने पर नीतिगत दरों में कटौती से वह हिचकेगा नहीं। इसलिए यह कोई चौंकाने वाला कदम भी नहीं है। इस साल सबसे पहले फरवरी, उसके बाद अप्रैल, जून और अगस्त में नीतिगत दरों में लगातार कटौती की गई थी। लेकिन आज भी उसका कोई सकारात्मक नतीजा नहीं नजर आ रहा है। अब रेपो दर एक दशक के सबसे निचले स्तर पर है। ऐसा भी पहली बार हुआ है जब साल में पांच बार नीतिगत दरों में कटौती का कदम उठाया गया हो।

बाजार में लंबे समय से बड़ी समस्या मांग नहीं होने से बनी है। इससे उत्पादन पर बुरा असर पड़ा है। माना जा रहा है कि ब्याज दरें और कम होने से लोग कर्ज लेंगे और कहीं न कहीं उद्योगों में जान आएगी। रीयल एस्टेट क्षेत्र भी रोशन हो सकता है। कुल मिलाकर सरकार के अर्थ-चक्र का गणित त्योहारी मांग पर केंद्रित हो गया है और वह भी खासतौर से घर और गाड़ियों की खरीद पर। अगर मांग निकलती भी है तो थोड़ी बहुत तेजी रीयल एस्टेट बाजार और ऑटोमोबाइल उद्योग में ही बनने के आसार हैं। लेकिन यह सोचने वाली बात है कि अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्रों का क्या होगा। त्वरित उपभोग वाला सामान बनाने वाली कंपनियां यानी एफएमसीजी क्षेत्र का क्या होगा जो कई महीनों से मंदी की चपेट में है। इसका वास्ता तो किसी त्योहारी मांग से नहीं होता। जबकि हाल में सरकार ने कारपोरेट करों में कटौती है और माना जा रहा है कि इससे भी कंपनियों के कारोबार में तेजी आएगी और बाजार गुलजार होंगे।

रिजर्व बैंक भी इस हकीकत को भलीभांति समझ रहा है कि मंदी का माहौल जल्दी पीछा नहीं छोड़ने वाला। नीतिगत दरों में बार-बार कटौती इस उम्मीद में ही की गई कि वाणिज्यिक बैंक ब्याज दरें घटाएंगे और इसका फायदा लोगों तक पहुंचेगा। कर्ज लेने वालों की तादाद बढ़ेगी। पर देखने में यही आया कि ज्यादातर बैंकों ने अपनी तिजोरी नहीं खोली और नीतिगत दरों के अनुरूप ब्याज दरों में कटौती नहीं की। इससे कर्ज सस्ता नहीं हुआ। अब रिजर्व बैंक ने इस बात पर सख्ती दिखाई है और यह अनिवार्य किया है कि ब्याज दरें नीतिगत दरों के अनुरूप ही रखी जाएंगी। अगर नीतिगत दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ता बाजार को नहीं मिलता है तो यह कदम निरर्थक साबित होता है। बैंक कर्ज सस्ते भले कर लें, लेकिन अब चौकन्ने हैं। खुल कर कर्ज बांटने से इसलिए बच रहे हैं, ताकि कहीं कर्ज डूब न जाए। छोटे उद्यमियों के लिए भी रिजर्व बैंक ने कर्ज की सीमा इसीलिए बढ़ाई है, ताकि उन्हें आसानी से कर्ज मिल सके और छोटे उद्योग रफ्तार पकड़ें। बाजार में नगदी संकट भी है। नोटबंदी के बाद से बैंकों में धन रखने को लेकर लोगों के मन में डर-सा बैठ गया है। इसलिए लोग जमा नगदी को निकालने से परहेज कर रहे हैं। पिछले दस-बारह महीने की मंदी ने लाखों लोगों का रोजगार छीन लिया है। इससे भी क्रय-शक्ति पर बुरा असर पड़ा है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस बार भी नीतिगत दरों में कटौती क्या बाजार में जान फूंक पाएगी!

आतंक का साया

इसमें कोई संदेह नहीं कि राजधानी दिल्ली सहित देश के दूसरे तमाम इलाकों में आतंकवादियों का सामना करने के लिए सुरक्षा बलों की तैयारी ऐसी है कि वे किसी भी आतंकी गतिविधि का सामना और उसे नाकाम कर सकते हैं। फिर भी यह चिंता की बात है कि सीमाई इलाकों में घुसपैठ के बाद अब आतंकियों के दिल्ली तक में आ धमकने की खबरें आई हैं। खुफिया सूचना के मुताबिक पिछले हफ्ते शहर में घुसे तीन से चार आत्मघाती आतंकी दरअसल जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हैं, जो जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने से बौखलाए हुए हैं और दिल्ली में बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में हैं। जाहिर है, यह अतिरिक्त सावधानी बरतने का समय है और इसी वजह से दिल्ली पुलिस के विशेष दस्ते ने बिना देरी किए एहतियाती कार्रवाई करते हुए कई जगहों पर छापा मारा और कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया। लेकिन यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जम्मू-कश्मीर में हुए घटनाक्रमों के बाद अलगाववादी संगठनों के भीतर किस तरह की हताशा छाई होगी और वे घात लगा कर नुकसान पहुंचाने की फिराक में होंगे।

लगभग दो महीने पहले जब जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के संदर्भ में जो फैसला लिया गया था, तभी से यह आशंका जताई जा रही थी कि इसके बाद वहां के आतंकी संगठनों की ओर से प्रतिक्रिया आ सकती है। इसीलिए केंद्र सरकार ने कश्मीर में अधिकतम और उच्च स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की और हालात के बेलगाम होने की आशंका के मद्देनजर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की। इन तमाम एहतियात की वजह से कश्मीर में कोई बड़ा विरोध सामने नहीं आया और उम्मीद की जा रही है कि कुछ दिनों में स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। लेकिन आतंकवादी संगठनों को शायद इसी बात से दिक्कत है कि इतने महत्त्वाकांक्षी फैसले के बावजूद कश्मीर में शांति क्यों बनी रही! शायद यही वजह है कि वे अब पहले की तरह आत्मघाती हमलों का रास्ता अख्तियार करके एक बार फिर घाटी को आतंक की आग में झोंकना चाहते हैं। लेकिन यह राहत की बात है कि देश के सुरक्षा बलों ने अब तक ऐसी हर अवांछित गतिविधि का वक्त पर सही जवाब दिया है और आतंकवादियों पर काफी हद तक लगाम लगी है।

यह किसी से छिपा नहीं है कि सीमापार से भारतीय इलाकों में घुसने की लगातार कोशिशों को सुरक्षा बलों ने किस तरह से नाकाम किया है। खासतौर पर पिछले कुछ समय से कश्मीर में घुसपैठ के मौके नहीं मिल पाने की वजह से आतंकवादियों के बीच हताशा का माहौल है। हाल के दिनों में यह साफ होकर उभरा है कि जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों के सरगना अपने पाकिस्तान स्थित ठिकानों से भारत में आतंकी गतिविधियां संचालित करते हैं। लेकिन भारत की तरफ से बार-बार इस ओर ध्यान दिलाने और शिकायत के बावजूद पाकिस्तान ने ऐसी कोई पहलकदमी नहीं की, जिससे उसकी सीमा से काम करने वाले आतंकी संगठनों को रोका जा सके। उल्टे पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मनमाने तरीके से कश्मीर का मुद्दा उठाया और भारत को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश की। लेकिन अब तक उसे दुनिया के किसी भी देश की ओर से ठोस समर्थन मिलना मुमकिन नहीं हुआ। जाहिर है, पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों के लिए इसे पचा पाना असहज है और वे भारत को दूसरे स्तर पर नुकसान पहुंचाने की मंशा रखते हैं। राजधानी दिल्ली में आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश इसी पृष्ठभूमि क नतीजा हो सकती हैं। इन आशंकाओं के मद्देनजर जरूरत इस बात की है कि सुरक्षा-व्यवस्था चाक-चौबंद हो और कोई भी ऐसी गुंजाइश नहीं छोड़ी जाए, जो बाद में किसी असुविधा का कारण बने।

कल्पमेधा

उन व्यक्तियों में मैं महानतम पद भी स्वीकार
नहीं करूंगा जो न तो सपने देखते हैं
और न ही इच्छाएं पालते हैं।
-खलील जिब्रान

समुद्र में बढ़ती भारत की ताकत

योगेश कुमार गोयल

पहले जहां युद्धपोतों के निर्माण क्षेत्र में सरकारी शिपयार्डों का ही एकाधिकार था और उन पर इनके निर्माण के लिए भारी दबाव भी रहता था, वहीं पिछले कुछ वर्षों से मेक इन इंडिया नीति के तहत निजी क्षेत्र द्वारा भी इस क्षमता को हासिल कर लेने के बाद इन जहाज कारखानों पर युद्धपोतों को बनाने का दबाव कम हुआ है और देश को अत्याधुनिक युद्धपोत भी समय से मिलने लगे हैं।

एक ओर जहां वायुसेना में शामिल हो रहे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान, हेलिकॉप्टर और मिसाइल प्रणालियां भारतीय वायुसेना को दिनों-दिन ताकतवर बना रही हैं, वहीं पिछले कुछ समय में भारतीय नौसेना में शामिल हुए अत्याधुनिक जंगी जहाज और पनडुब्बियां भी भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में सक्षम हैं। वर्ष 2008 के मुंबई हमले के बाद भारत के पश्चिमी समुद्री तट की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने कई सुरक्षात्मक कदम उठाए हैं, जिनमें से समुद्री सीमा में अपतटीय गश्ती पोतों की तैनाती भी प्रमुख है। पिछले कुछ समय में अंडमान-निकोबार द्वीप से लेकर म्यांमा की सीमाओं तक चीन ने अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ाई हैं। इस वजह से भी हिंद महासागर में सुरक्षा बढ़ाना भारत के लिए अनिवार्य हो गया है। यही कारण है कि देश की समुद्री सुरक्षा को चाक-चौबंद करने के लिए रक्षा मंत्रालय नौसेना को अत्याधुनिक समुद्री जहाजों, पनडुब्बियों और नावों से लैस करने में जुटा है।

चीन 'वन बेल्ट वन रोड' योजना के तहत हिंद महासागर में गतिविधियां बढ़ा रहा है। चीन के इस बढ़ते दबदबे को लेकर भारत सहित दुनिया के कई देशों में चिंता होना स्वाभाविक है। इस योजना के तहत चीन एशिया और अफ्रीका के कई देशों में अपनी नौसेना की मौजूदगी बढ़ा रहा है। इसी के चलते पिछले साल भारत और फ्रांस के बीच 'मैरीटाइम अवेयरनेस' समझौता भी हुआ था, जिसके तहत दोनों देश नौसैनिक अड्डों पर युद्धपोत रख सकेंगे। फ्रांस के साथ यह समझौता इसलिए महत्त्वपूर्ण है कि उसके पास ताकतवर समुद्री सेना के अलावा परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बियां भी हैं।

पिछले दिनों गश्ती पोत 'वराह' को तटरक्षक बल में शामिल किया गया था। अनठानवे मीटर लंबाई वाले गश्ती पोत वराह का डिजाइन और निर्माण देश में ही किया गया है, जो तलाश, बचाव कार्य और समुद्री गश्ती संचालन के लिए दो इंजन वाले हेलिकॉप्टर और तीव्र गति की चार नौकाओं को ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा इसमें समुद्र में तेल फैलने जैसी घटनाओं से बचाव के लिए प्रदूषण नियंत्रक उपकरण भी लगे हैं और यह चिकित्सा सुविधाओं, अत्याधुनिक नौवहन, मशीनरी, सेंसर और आधुनिक निगरानी प्रणालियों से लैस है। आइसीजीएस 'वराह' पर 30 एमएम और 12.7 एमएम की बंदूकों से लैस है। इस पोत में एकीकृत निगरानी प्रणाली, स्वचालित ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली, उच्च क्षमता की अग्निशमन प्रणाली, स्वदेश निर्मित एकीकृत पोत प्रबंधन प्रणाली लगी है। 'वराह' तटरक्षक बल के सात समुद्री गश्ती पोत की शृंखला में चौथा है।

पहले जहां युद्धपोतों के निर्माण क्षेत्र में सरकारी शिपयार्डों का ही एकाधिकार था और उन पर इनके निर्माण के लिए भारी दबाव भी रहता था, वहीं पिछले कुछ वर्षों से मेक इन इंडिया नीति के तहत निजी क्षेत्र द्वारा भी इस क्षमता को हासिल कर लेने के बाद इन जहाज कारखानों पर युद्धपोतों को बनाने का दबाव कम हुआ है और देश को अत्याधुनिक युद्धपोत भी समय से मिलने लगे हैं। वर्ष 2014 में रक्षा मंत्रालय ने एलएंडटी शिपयार्ड लिमिटेड को सात तटीय पोतों के डिजाइन बनाने से लेकर निर्माण तक की जिम्मेदारी दी थी, जिनमें से चार को निर्धारित समय से पहले ही तैयार कर लिया गया और पांचवें तटीय गश्ती पोत 'वरद' को भी अगले कुछ हफ्तों में समुद्री परीक्षण के लिए तैयार कर लिए जाने की संभावना है। तटरक्षक बल में शामिल हो चुके अन्य तीन युद्धपोतों में आईसीजीएस विक्रम को सिर्फ पच्चीस महीने के भीतर तैयार कर पिछले वर्ष तटरक्षक बल को सौंप दिया गया था। यह पांच हजार समुद्री मील का सफर तय कर सकता है और इस पर हेलिकॉप्टर भी तैनात किए जा सकते हैं। इसके जरिए भारत के द्वीपीय भूभागों की चौकसी के अलावा समुद्री डाकुओं पर भी नजर रखी जा सकती है। इसी तरह आइसीजीएस विजय नामक पोत को भी पिछले साल अप्रैल में नौसेना को सौंप दिया गया था।

पिछले साल ही गश्ती पोत 'आइसीजीएस वीरा' को भी तटरक्षक बेड़े में शामिल किया गया था। इस जहाज को एक जुड़वां इंजन वाले हेलिकॉप्टर और चार उच्च गति वाली नौकाओं को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें बोर्डिंग ऑपरेशन, खोज, बचाव, कानून प्रवर्तन और समुद्री गश्त के

लिए दो नावें भी शामिल हैं। ऐसे ही पोतों में आइसीजीएस शौर्य और आइसीजीएस समर्थ भी शामिल हैं। इस समय जितने भी गश्ती पोत बनाए जा रहे हैं, वे सभी स्वदेशी डिजाइन वाले अत्याधुनिक संचार तंत्र, अरपा रडार, चुंबकीय कंपास, स्वचालन की सुविधा, इलेक्ट्रिक चार्ट डिस्प्ले, इको साउंडर इत्यादि सुविधाओं से लैस होंगे।

जहां तक हाल में मुंबई के समुद्र तटों की रक्षा के लिए नौसेना में शामिल हुई पनडुब्बी आइएनएस खंडेरी की बात है तो यह नौसेना की दूसरी सबसे अत्याधुनिक पनडुब्बी है। प्रोजेक्ट-75 के तहत देश के भीतर बनी स्कॉर्पियन श्रेणी की पहली पनडुब्बी आइएनएस कलवरी थी और आइएनएस खंडेरी इसी श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी है। मुंबई के मझगांव डॉक में बनी खंडेरी का वर्ष 2017 में जलावतरण हुआ था, सागर की गहराइयों में दो साल तक परीक्षण करने के बाद देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए खंडेरी को तैनात किया गया है। यह किसी भी युद्धपोत को ध्वस्त करने की अद्भुत क्षमता रखती है। अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित स्वदेशी पनडुब्बी खंडेरी को भारतीय समुद्री सीमा की सुरक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम इसीलिए माना जा रहा है कि यह मुंबई के तट पर रहकर ही तीन सौ किलोमीटर दूर स्थित दुश्मन के जहाज को नष्ट करने की क्षमता रखती है और इसीलिए इस पनडुब्बी के नौसेना के शामिल होने से नौसेना की ताकत पहले के मुकाबले काफी बढ़ गई है। जंग के दौरान पानी में दुश्मन पर सबसे पहले प्रहार करने वाली कलवरी श्रेणी की यह दूसरी डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है।

यह एक बार में पैंतालीस दिनों तक बारह हजार किलोमीटर का सफर तय करने और समुद्र में करीब साढ़े तीन सौ मीटर की गहराई में जाकर गोता लगाने में सक्षम है। यह समुद्र के अंदर करीब 20 समुद्री मील और पानी के ऊपर ग्यारह समुद्री मील की रफ्तार से चलने में सक्षम है। विशेष प्रकार के स्टील से बनी इस पनडुब्बी में उच्च तन्यता शक्ति है, जो अधिक गहराई में जाकर काम करने की क्षमता रखती है। खंडेरी विभिन्न प्रकार के अभियानों जैसे सतह-रोधी युद्धक क्षमता, पनडुब्बी-रोधी युद्धक क्षमता, खुफिया जानकारी जुटाना, क्षेत्र की निगरानी करने जैसे कामों में पूरी तरह सक्षम है। खंडेरी को 'साइलंट किलर' कहा जाता है, क्योंकि यह विश्व की सबसे शांत पनडुब्बी है जिसमें रडार, सोनार, इंजन सहित छोटे-बड़े एक हजार से भी अधिक उपकरण लगे होने पर भी यह बिना आवाज किए पानी में चल सकती है। रडार से बच निकलने की यह विशेष क्षमता इसे अन्य कई पनडुब्बियों की तुलना में अभेद्य बनाने में बेहद महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। खंडेरी के बाद जल्द ही आइएनएस करंज भी नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगी।

रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन पिछले कुछ वर्षों से जिस प्रकार अपना नौसेना खर्च बढ़ा रहा है, उसे देखते हुए भारतीय नौसेना को भी तेजी से आधुनिकीकरण की जरूरत है। अमेरिकी सुरक्षा विभाग पेंटागन की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि कुछ महीने पहले ही चीन ने बड़ी संख्या में परमाणु मिसाइल पनडुब्बियों को नौसेना में शामिल किया है। इससे भारत के लिए खतरा और चुनौती ज्यादा बढ़ गई है।

हम छत पर हैं

पूनम पांडे

दुनिया मेरे आगे

मीठी-मीठी गुलाबी सर्दी के संकेत आने लगे हैं। इसके साथ ही छत पर टहलना, ठहरना बहुत अच्छा लगने लगा है। कुछ दिनों के बाद से जनवरी तक हर जगह छतों पर खिलखिलाहट बिखरने लगेगी। ऐसा लगेगा कि छतें आबाद हो रही हैं। छतें सचमुच जीवन की कहानियां सुना कर जीवन जीने के लिए तैयार करती हैं। जीवन का इतना रस देकर भी, खुशी के मोती लुटा कर भी छतें सदियों से वैसी ही निश्छल हैं। एक यात्रा के दौरान कई शहरों में थोड़ी-थोड़ी देर ठहरते हुए वहां की अल्हड़ रवानगी को खूब महसूस किया। वहां की छतों पर जीवन का ताना-बाना पूरी मस्ती में तरंगित होता दिखा। ऐसा लगा कि पतंग उड़ाते बच्चों के साथ छत अपना घूंघट उठा कर लहालोट हो रही हो। संस्कृति की आबोहवा का पूरा रंग रास्ते भर छतों से हमारी तरफ छलकता हुआ दिखाई दिया और यात्रा पूरी करने तक धड़कनों में रहा भी। गांव और कस्बों में छतों पर उल्लास देख कर समझ में आता है कि जीवन की उमंग और तरंग किसी खास सुविधा की मोहताज नहीं है।

ऐसे नजारे देखने को मिल जाते हैं कि बड़ी मंगौरी तोड़ती, चिप्स-पापड़ सुखाती, बच्चों के साथ अठखेलियां करती, छत पर लगाए पौधों की हरियाली से सीमेंट की छत को बागबां कर रही महिलाएं ऊर्जा से भरी लगती हैं। भरपूर हवा और रोशनी में प्रकृति का संग कितना अनूठा लगता है! मनुष्य के दिमाग की बनावट ऐसी जटिल है कि आधुनिक जगत की निजता और मशीनीपन ने लुटेरे की तरह उसके बिंदास मन की तरंगों को छीन लिया है। महानगरों के ऊंचे अपार्टमेंट के अकेले बंद घरों में बोन्साई जैसे बच्चे ऐसी छत की दोस्ती का मजा कहां लूट पाते हैं! सुबह-शाम छतों पर दौड़ना कितनी ताजगी से भर देता है, यह वे क्या जानें जो कमरे में बैठ कर मोबाइल और टैब के शिकंजे मे फंसे हुए हैं।

प्रेम, आत्मीयता, आपसी जुड़ाव कितना महत्त्वपूर्ण होता है, इसे छत पर अधिक समय गुजारने वाले लोग बखूबी समझते हैं। लेकिन आज हमारे पास छत पर जाकर बैठने का समय ही कहां है! वे आत्मीय रिश्ते जो एक छत से दूसरी छत तक हवा के झोकों की तरह महसूस किए जाते थे, अब सोशल मीडिया के 'स्माइली' बन कर दम तोड़ रहे हैं। बरामदे और बालकनी के बाद भावों के संगम की तीसरी नदी है तो वह है छत! अकेलापन हर लेती छतें बहुत ही लावण्यमयी और बेहद मधुरिम भी हैं। पहले सुबह से दोपहर और शाम से रात तक कितने ही बहाने होते थे कि हम कभी छत पर जा बैठते, कभी भोजन करने के बाद आराम भी फरमा लेते थे। परिंदों को दाना-पानी देने के लिए भी छत का एक हिस्सा हमेशा तय होता था। 'छतें हमारे लिए मनोरंजन थीं और दीवारों से रहित अपने सरीखी दुनिया भी', रामपुर के किले के पास ही बतियाते हुए एक महिला ने जब यह कहा तो बचपन की छत मुझे मेरे दिल में दिखाई दे गई।

रिश्तों की दुनिया में आधे से ज्यादा दिक्कतों की वजह एक ही है कि मन को खोलते तो सब हैं, लेकिन मन की किताब को कम ही लोग पढ़ पाते हैं। बादल को अगर पानी कह दिया जाए तो मन भीग नहीं जाता। हमारे बचपन की छत पर बैठने वाली बुआ-चाची छतों पर ही एक-दूसरे को साफ-साफ बताती थीं अपनी दबी हुई सिसकी का असली कारण। ओढ़ी हुई हंसी की असली वजह और इस तरह एक-दूसरे से जुड़ी रहती थीं छतों में। उनकी एक अपनी ही दुनिया होती थी।

काफ्का का दर्शन है या मार्खेज का जादुई यथार्थवाद या फिर ओशो का अनूठा चिंतन, हम सबके भीतर एक किताब होती है वह बात जो चैन से सोने नहीं देती। पेड़ों के झुरमुट से झांकती है, समंदर की लहर बन कर पैरों से टकराती है, ताक-झांक करती है, मन के दरवाजे पर खटखटाती है, मगर उस आवाज पर गौर न करने से वह किताब अपने पन्नों सहित हो जाती है बिल्कुल खामोश! अगर आप पैंतीस से चालीस की उम्र के आसपास हैं तो कहीं न कहीं, आपने भी अपनी किशोरावस्था के दौरान किसी छत पर मन की ऐसी ही चुप्पियों को मुखर होते हुए देखा होगा। एक बुजुर्ग दादी ने मुस्करा कर बताया- 'काश! फिर से महफिल जमने लगें छत पर... फिर कुछ अपनापन लौट आए कि वे पल जिंदादिल लगें। यह एक अधूरी उम्मीद ही तो है, जिसके सहारे हम बूढ़े होकर भी बूढ़े नहीं होते।'

आजकल दुनिया में बहस के बीच होना इतनी बड़ी बात नहीं है, मगर उसमें न कूद पड़ना कहीं ज्यादा बड़ी बात है। इसीलिए उम्मीद और बुजुर्ग दादी की बातों में छत को खोजने का सिलसिला जारी रहेगा। महसूस करना होगा कि छत अपने को गंभीरता से नहीं लिए जाने का हिसाब मांगती है। कई बार थोड़ी देर के लिए चले जाना बहुत देर के लिए लौट आने की तैयारी के लिए बहुत जरूरी होता है। चले जाने से पैदा हुई एक खाली जगह में नई दुनिया बन कर लौट आने की गुंजाइश होती है। छतों का यह दर्शन बड़ा मनभावन है।

चौपाल

आपदा को न्योता

बाढ़ को हमेशा से प्राकृतिक आपदा के रूप में गिना जाता रहा है लेकिन हमें सोचना चाहिए कि जंगलों का विनाश तो प्राकृतिक नहीं है, कंक्रीट के जंगल प्राकृतिक नहीं हैं, नदियों पर बांध प्राकृतिक नहीं हैं और न ही वैश्विक तापमान का बढ़ना प्राकृतिक है। विकास की अंधी दौड़ में जंगलों का नाश हुआ, आधुनिक नगर बसे, उद्योगों का विकास हुआ, वैश्विक तापमान बढ़ा और जलवायु में परिवर्तन हुआ। और इन्हीं सब कारणों से बाढ़ जैसी आपदाओं की बारंबारता बढ़ी। बाढ़ पहले भी आती थीं लेकिन अब इनकी आवृत्ति से लगता है कि मानव ही इन्हें बुलाता है। बाढ़ का मुख्य कारण प्राकृतिक कम और मानव जनित ज्यादा प्रतीत होता है।

वैश्विक जलवायु में परिवर्तन और तापमान में वृद्धि के कारण ही वर्षा के समय में भी परिवर्तन हुआ है। पहले तीन ही मुख्य मौसम होते थे पर अब कई मौसम हैं। जैसे प्रचंड गर्मी है, वैसे ही ठंड है। बेमौसम बारिश का नतीजा भी बाढ़ के रूप में सामने आता है। आधुनिक शहरों का कुप्रबंधन भी बाढ़ का मुख्य कारण है, वरना तीन घंटे की बारिश में मुंबई में बाढ़ कैसे आ सकती है?

जल प्रबंधन तथा आपदा प्रबंधन के साथ-साथ कुछ महत्त्वपूर्ण उपायों के जरिए बाढ़ से बचा जा सकता है। बहुचर्चित नदी जोड़ परियोजना से बाढ़ की बारंबारता और सूखने वाली नदियों को आपस में जोड़ कर अतिरिक्त जल का प्रबंधन किया जा सकता है। छोटे व बड़े स्तर पर 'वाटर हार्वेस्टिंग' तकनीक के व्यापक और अनिवार्य क्रियान्वयन से अतिरिक्त जल को सीधे भूमि में स्थानांतरित किया जा सकता है, जिससे बाढ़ से राहत तो मिलेगी ही, भूमिगत जल का स्तर भी बढ़ेगा। बाढ़ को सहने योग्य अधोसंरचना का अधिकतम निर्माण होना चाहिए जिससे बाढ़ के समय जानमाल का नुकसान कम होगा। जंगलों का संरक्षण आज के समय में अनिवार्य जरूरत है। ये जंगल ही हैं जो बाढ़ के प्रभाव को कम करते हैं। आधुनिक और नवीनतम तकनीकों का प्रयोग, जैसे इसरो व भारतीय मौसम केंद्र की सहायता से बाढ़ का समय-पूर्व आकलन, बैंकिंग आदि वित्तीय संस्थाओं के प्रयोग से राहत कार्य का पैसा जरूरतमंद को तुरंत पहुंचाना आदि।

हम समझ सकते हैं कि बाढ़ एक मानव जनित आपदा के तौर पर विकराल रूप लेती जा रही है और बचाव का एकमात्र साधन यह है कि हमें विकास की दौड़ में प्रकृति को साथ लेकर चलना ही होगा। प्रत्येक व्यक्ति की ओर से थोड़ी-सी समझदारी, जागरूकता और पहल से व्यापक बदलाव लाया जा सकता है।

● *जितेंद्र साहू, शहडोल, मध्यप्रदेश*

संतुलन जरूरी

व्यक्तिगत स्वतंत्रता और देश की सुरक्षा में संतुलन जरूरी है। इसमें संदेह नहीं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता महत्त्वपूर्ण है, लेकिन इस हद तक नहीं कि देश की सुरक्षा की अनदेखी कर दी जाए। इससे इनकार नहीं कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद घाटी में कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन इनका मकसद लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करना नहीं, बल्कि शांति एवं व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इसे सुनिश्चित करने में इसलिए बाधाएं आ रही हैं कि कुछ लोग अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे तत्त्वों पर लगाम लगाना सरकार का दायित्व है। इसी तरह उन तत्त्वों पर भी लगाम लगाना आवश्यक है जो न केवल अलगाववादियों और आतंकवादियों की भाषा बोलने में लगे हुए हैं, बल्कि उनके हितैषी भी बने हुए हैं।

● *हेमंत कुमार, गोराडीह, भागलपुर, बिहार*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

इंदौर की नजीर

इस साल गांधी जयंती से देश में एकल इस्तेमाल वाले प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है, जो बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में सहायक होगा। स्वच्छता के मामले में लगातार तीन बार पहले स्थान पर रहने वाले इंदौर शहर ने तो प्लास्टिक और पॉलीथिन के खिलाफ पिछले तीन वर्षों से मोर्चा खोल रखा है। इंदौर के कई बाजार आज प्लास्टिक के उपयोग को पूरी तरह प्रतिबंधित कर चुके हैं। इंदौर नगर निगम ने अनूठी पहल करते हुए एक बर्तन बैंक भी शुरू कर दिया है। इसमें पांच-पांच सौ नग थाली, कटोरी, गिलास, जग और प्लेटें जमा करके लोगों को आयोजनों के लिए निशुल्क देना शुरू किया है। इससे तीन माह की अल्प अवधि में ही लगभग दस टन एकल इस्तेमाल प्लास्टिक का उपयोग रुका जो एक मिसाल है। यदि इंदौर का अनुसरण कर देश के अन्य शहरों में भी इस तरह के बर्तन बैंक शुरू किए जाए तो टनों प्लास्टिक और पॉलीथिन का उपयोग रोका जा सकता है।

● *संजय डागा, हातोद, इंदौर*

गलत क्या

पिछले दिनों एक खबर के नकारात्मक पक्ष पर तो ध्यान दिया गया लेकिन उसकी सकारात्मकता सुर्खियां नहीं बन पाई। मध्यप्रदेश के खंडवा जिले के प्राथमिक स्कूल सिहाड़ा में बच्चों से टॉयलेट साफ कराने का जो वीडियो वायरल हुआ था उस पर विवाद खड़ा हो गया। लेकिन इस विवाद का सबसे सकारात्मक पक्ष यह रहा कि कलेक्टर तन्वी सुंद्रियाल ने कहां कि सारे बच्चे टॉयलेट तो क्या, स्कूल भी साफ करें तो इसमें गलत क्या है! उन्होंने जापान की मिसाल देते हुए कहा कि वहां बच्चे स्कूल के हर काम में लगे रहते हैं तो उन्हें लगता है कि यह स्कूल मेरा है, इसे मैं गंदा नहीं कर सकता। आज स्कूलों में बच्चों से साफ-सफाई कराने पर फोटो व समाचार छप जाते हैं और अनावश्यक विवाद पैदा कर दिया जाता है।

हमारे देश की गुरुकुल परंपरा में तो राजा-रंक सभी अपनी शिक्षा-दीक्षा के समय आश्रम की साफ-सफाई करना, पानी लाना, जंगल से लकड़ी लाना या अन्य काम करते थे क्योंकि यह शिक्षा भी जीवनोपयोगी है। जब स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया तो प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों को सफाई के प्रति जागरूकता का संदेश दिया था तो स्कूलों में साफ-सफाई कराने में क्या बुराई है! इसे सकारात्मक चश्मे से देखना जरूरी है।

● *हेमा हरि उपाध्याय अक्षत, खाचरोद, उज्जैन*

epaper.jansatta.com